राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 156वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **10.03.2023** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **156वीं** बैठक **श्री अजय कुमार खुराना**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री रोहित गुप्ता, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार, श्री महेंद्र कुमार पारख, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री बी.के. त्रिपाठी, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री कमलेश कुमार चौधरी, संयोजक, एसएलबीसी राजस्थान और महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री विकास अग्रवाल, उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुधांशु खमारी, उपमहाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

श्री कमलेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 156वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

LDM, DDM, RSETI Directors की Conclave: राजस्थान में पहली बार LDM, DDM, RSETI Directors की Conclave का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 2023 माह में उदयपुर में किया गया जिसमें राज्य के सभी जिलों के सर्वांगीण आर्थिक विकास में LDM, DDM, RSETI Directors के दायित्वों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

उक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/सुझाव निम्नानुसार हैं-

- **Strengthening of Lead District Managers-** एलडीएम के रूप में केवल dynamic & carrier oriented बैंकिंग कर्मियों को पदस्थापित किया जाये, उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा, पर्याप्त कर्मचारी और वाहन एवं उचित ट्रेनिंग प्रदान की जाए।
- **Annual Credit Plan-** जिलों के PLP एवं ACP के लक्ष्यों में समरूपता रखी जाये एवं आगामी वित्तीय वर्ष (2023-24) में ACP के लक्ष्य, PLP के सापेक्ष रखा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बैंकों के वार्षिक ACP लक्ष्य, उनके प्रधान कार्यालयों से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार ही होने चाहिए।
- **R-SETI-**
  - आर-सेटी निदेशक अपने अधीन आर-सेटी में चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नये रोजगार सृजन करने पर विशेष ध्यान दे एवं चलाये जा रहे कार्यक्रमों में विविधता लाये।
  - प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन व ऑफलाइन बाजारों से जोड़ने एवं उनके उत्पादों के मार्केटिंग और बिक्री करने में सहयोग प्रदान करें। सभी आर-सेटी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण एवं क्रेडिट लिंकेज करने हेतु भी विशेष प्रयास करें।

<u>LDM Rating Matrix</u>- LDM, DDM, RSETI Directors की Conclave में दिसम्बर, 2022 तिमाही के आकड़ों के आधार पर की गयी एलडीएम की त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 3 एलडीएम को पुरस्कृत किया गया।

<u>Financial Literacy Week (वित्तीय साक्षरता सप्ताह, 2023)-</u> भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह-2023 का आयोजन **'Good Financial Behaviour- Your Saviour'** अर्थात **'सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव'** की **Theme** पर दिनांक 13 फरवरी से 17 फरवरी, 2023 तक किया गया। इस कार्यक्रम की **sub-theme** '**Active Saving, Planning & Budgeting'** एवं '**Prudent use of Digital Financial Services'** रहीं। सप्ताह के दौरान बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं FLCs द्वारा वित्तीय साक्षारता शिविरों का आयोजन किया गया। सप्ताह के अंत में चित्तौडगढ़ जिले में वृहद वित्तीय साक्षारता शिविर का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अग्रणी जिला कार्यालय के सहयोग से किया गया, जिसमे 500 से अधिक महिलाओं, पुरुषों, छात्र-छात्राओं, किसानों आदि के द्वारा सहभागिता की गई।

<u>International Women's Day, 2023-</u> राज्य सरकार एवं नाबार्ड के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर साप्ताहिक समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह के तहत दिनांक 08.03.2023 "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के उपलक्ष्य में "राज्य स्तरीय महिला आर्थिक सशक्तिकरण" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूह इत्यादि महिला-केन्द्रित योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए।

<u>Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna</u>- राजस्थान सरकार कि फ्लैगशिप स्कीम इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में पिछली एसएलबीसी बैठक तक 5.00 लाख खातों के सापेक्ष (09 दिसम्बर 2022) मात्र 42,765 खातों (8.56%) में ऋण वितरण किया गया था। दिनांक 01.03.2023 को बढ़कर 1.81 लाख खातों (36.18%) में ऋण वितरण कर दिया गया है।

उन्होने एसएलबीसी की अगली त्रैमासिक बैठक से पूर्व सदस्य बैंकों से निम्नानुसार प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया-

- राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना "इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना" और अन्य योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के एसीपी लक्ष्यों की उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समयबद्ध तरीके से वार्षिक साख योजना की तैयारी।
- कृषि में निवेश ऋण को 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाना।
- PMJJBY, PMSBY, APY, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, PMFME, AIF जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों की उपलब्धि।
- प्रति व्यक्ति आय बढ़ते हुये गरीबी कम करने पर विशेष ध्यान देना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने सदन को संबोधित करते हुए बताया की -

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक, बैंकों ने **15.3 प्रतिशत** (Y-O-Y) की ऋण वृद्धि और **9.2 प्रतिशत** (Y-O-Y) की जमा वृद्धि दर्ज की।
- **Brick & Mortar Branches**: DFS, MoF, GoI के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए **95** स्थानों को चिन्हित किया गया है। जिनमें से **78** केन्द्रों पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं अथवा आवंटन के बाद खोली गई हैं। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे शेष स्थानों पर अर्थात उन्हें आवंटित **17** स्थानों पर जल्द से जल्द शाखाएं खोलें।

(कार्यवाही: बंधन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)

राज्य में **सदस्य बैंकों के प्रदर्शन** के संदर्भ में, उन्होने सभी सदस्य बैंकों को वर्ष 2022-23 में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जैसे-

- **अटल पेंशन योजना** के तहत **107.00%** लक्ष्य उपलब्धि **(15 फरवरी, 23 तक)**
- **PMEGP** के तहत लक्षित मार्जिन राशि के विरुद्ध **149.00%** स्वीकृति **(01 मार्च, 23 तक)**
- **IMSUPY** के तहत आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध **94.00%** स्वीकृति **(17 फरवरी, 23 तक)**

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अति-महत्वपूर्ण मार्च तिमाही में प्रदर्शन में सुधार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की निम्नानुसार अपील की-

- वार्षिक साख योजना के शेष लक्ष्यों की प्राप्ति।
- PMJJBY, PMSBY, APY जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति।
- PM- SVANidhi, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, PMFME, Agriculture Infrastructure Fund के तहत आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

साथ ही उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे राज्य के विकास हेतु राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में अपना योगदान प्रदान करें। जैसे कि

- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रत्साहन योजना

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होने राज्य के विभिन्न key indicators पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- दिसंबर 2022 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का कुल कारोबार **रुपये 11.08 लाख करोड़** के स्तर पर पहुंच गया है। बैंकों ने जमा में **11.75%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाई है और अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि **18.6%** है।

- राज्य का सीडी अनुपात दिसंबर, 2022 तक **88.51%** है और यह RBI बेंचमार्क से काफी ऊपर है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिमों ने **11.31%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है जो संतोषजनक है और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों में दिसंबर, 2021 की तुलना में **9.31%** की वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक ACP के तहत वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि **90.46%** है एवं एमएसएमई के तहत ACP की उपलब्धि **119.40%** है।

साथ ही उन्होने राज्य सरकार से बैंकों से संबन्धित लंबित निम्नलिखित प्रकरणों पर समर्थन देने हेतु अनुरोध किया:

- सब्सिडी वाली विभिन्न सरकारी ऋण योजनान्तर्गत बैंकों की बकाया राशि को शामिल करने हेतु **PDR अधिनियम, 1952** में संशोधन लंबे समय से लंबित है। उन्होने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से PDR अधिनियम, 1952 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि बैंक ऋण वसूली में तेजी लाई जा सके और सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में बढ़ते NPA को कम किया जा सके।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- उन्होने भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि **कृषि ऋण रहन पोर्टल** पर राज्य के सभी जिलों की onboarding को पूरा करें और इसकी तकनीकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। उन्होने संबंधित विभाग के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि बैठक के दौरान इस संबंध में हुयी कोई भी प्रगति से सदन को अद्यतित करें।

(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

- **RSETI** से संबंधित **भूमि आवंटन** का मामला राज्य सरकार के पास 7-8 वर्षों से लंबित है। उन्होने राज्य सरकार के संबन्धित सदस्यों से बैठक के दौरान वर्तमान स्थिति से सदन को अवगत करवाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

- आर-सेटी द्वारा SRLM, GoR को प्रशिक्षण संबंधी खर्चों के भुगतान हेतु प्रस्तुत बकाया दावे की गैर-मंजूरी का मामला लंबे समय से लंबित है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-RODA Act) के तहत, लगभग **रु 3,288 करोड़** रुपये के **1.47 लाख** RODA मामले जिला/ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं और **रु 2,129 करोड़** से अधिक राशि के **0.99 लाख** से अधिक मामले **एक वर्ष** से अधिक समय से लंबित हैं। बैंक की एनपीए वसूली के पक्ष में माहौल बनाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सरफेसी अधिनियम के मामलों में अनुमति प्रदान करने में असामान्य देरी का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। इस संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी भी लगभग **रु 414 करोड़** के **2,085** प्रकरण

जिला प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से **रु. 338 करोड़** के **1,532** मामले लगभग **60** दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- RODA और SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में वसूली को गति देने के लिए, यह सुझाव है कि राज्य में एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।

उन्होने सदस्य बैंकों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समयबद्ध तरीके से वार्षिक साख योजना तैयार करने में अग्रणी जिला प्रबंधकों सहयोग प्रदान करने और ACP को PLP-ACP-Corporate लक्ष्य के अनुरूप रखना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही निम्न बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया-

1. केसीसी संतृप्ति अभियान में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना।
2. कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण (Investment Credit) में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
3. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना।
4. 'डिजिटल वित्तीय साक्षरता' के प्रसार पर ध्यान देना।

अंत में उन्होने राज्य में विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में समन्वय हेतु केंद्र / राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन का संबोधित करते हुये कहा कि-

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र से संबन्धित योजनाएँ सरकार की flagship योजनाएँ होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी बैंक इनमे अपना पूर्ण योगदान देते हुये इन योजनाओं के लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- नवीनतम बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सहकारी क्षेत्र में गैर-कृषि क्षेत्र के लिये राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका कार्यान्वयन सहकारी बैंकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। किन्तु वाणिज्यिक बैंकों की इस योजना में प्रगति नगण्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अनुरोध है कि बैंकों को उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्य आवंटित करें। बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजनांतर्गत प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक)

- इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को उद्योग शुरू करने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का योजनान्तर्गत प्रदर्शन सराहनीय है। किन्तु अधिकांश बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है। बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि भी समान्यतः बहुत कम होती है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत संतोषजनक प्रदर्शन करने हेतु अधिक प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होने महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2023 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के उपलक्ष्य में "राज्य स्तरीय महिला आर्थिक सशक्तिकरण" पर आयोजित कार्यशाला में सहभागिता करने हेतु सभी बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञपित किया। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि यदि उक्त सभी योजनाओं में किसी स्पष्टता एवं सहयोग की आवश्यकता हो तो वह विभाग को सूचित करें।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उस पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना का पोर्टल चालू नहीं हुआ है।
- योजनान्तर्गत गैर-कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाला ऋण cash credit के रूप में दिया जाएगा जिसका लाभार्थी को हर वर्ष के अंत में खाते में बकाया राशि जमा करके ऋण को अगले साल के लिए नवीनीकृत करवाना होगा। लाभार्थी यह राशि कैसे 1 वर्ष में जमा करवा कर roll-over करवा पाने में समर्थ होंगे, यह चिंता का विषय है।
- योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले 10% ब्याज अनुदान पर सरकार द्वारा अभी तक निर्णयात्मक निर्णय नहीं हुआ है।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- आई-टी विभाग, राजस्थान सरकार राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना का पोर्टल जल्द-से-जल्द चालू करने हेतु प्रयासरत है। सभी बैंकों से निवेदन है कि तब तक offline माध्यम से आवेदन प्राप्त करके ऋण स्वीकृति एवं वितरण करें।
- योजनान्तर्गत गैर-कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले cash credit के roll-over से संबन्धित व्यावहारिक चुनौती के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है। जिसके संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सभी बैंक योजना को राज्य में लागू करें एवं भविष्य में उक्त समस्या के अतिरिक्त बैंकों को आने वाली अन्य किसी समस्या के समाधान हेतु यथानुसार योजना में संशोधन कर दिये जायेगे।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने निम्नानुसार सदन को सूचित किया-

- राज्य में लगभग 2,200 गाँवों में 5 किमी की परिधि में बैंक शाखा अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कार्यरत नहीं है। वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार बैंक मित्रों को banking outlet के रूप में नहीं मानते। बैंकों से अनुरोध है कि इन ग्रामों में बैंक शाखाएँ खोलें। मुख्य सचिव महोदया ने पत्र के माध्यम से बैंकों को आश्वासन दिया है कि बैंक शाखा खोलने हेतु उचित स्थान नहीं मिलने पर पंचायत भवन, इत्यादि स्थानीय सरकारी भवनों में स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
- आकांक्षी ज़िलो के बाद सरकार अब सभी जिलों में Aspirational Block Programme के तहत चयनित ब्लॉक (Selected Blocks) में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि सरकार की इस पहल में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

- वित्तीय साक्षारता एवं डिजिटल साक्षारता की दिशा में प्रयासों में वृद्धि करें।
- सभी बैंक वार्षिक साख योजना समेत राज्य सरकार की समस्त flagship योजनाओं, जैसे IGSCCY, IMSUPY, MLUPY इत्यादि एवं नाबार्ड की कृषि प्रधान योजनाओं में लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित करें।
- उक्त योजनाओं के तहत जो ऋण स्वीकृत कर दिये गए हैं उनमे ऋण वितरण चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- बैंक मित्रों की कार्य-कुशलता एवं दक्षता चिंता का विषय है। साथ ही सभी बैंक मित्रों द्वारा सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। बैंक मित्रों एवं Corporate BCs की बेहतर निगरानी किया जाना आवश्यक है। साथ ही बीसी पॉइंट्स पर किए जाने वाले लेन-देन की transaction cost को कम करने की दिशा में सभी हितग्राहकों को कदम उठाने की आवश्यकता है।
- किसान ऋण माफी योजना में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभी तक उचित निर्णय नहीं लिया गया है।
- राज्य सरकार बैंकों से संबन्धित सभी लंबित मुद्दों का समाधान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि कृषि ऋण माफी योजना बैंकों का नीतिगत मुद्दा है जिसका formula बैंक बोर्ड द्वारा अनुमत किया जाएगा। उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संबन्धित हितग्राहकों एवं राज्य सरकार के संबन्धित अधिकारियों के बीच बैठक के माध्यम से इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने की अनुशंसा की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंकों से निम्नानुसार अनुरोध किया-

- सभी सरकारी योजनाओं में बैंकों द्वारा सराहनीय योगदान किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार इन योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सरकारी व्यवसाय प्रदान कर के उनका उत्साह वर्धन करने की दिशा में विचार कर रही है।
- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने हाल ही में नई पहल की हैं, जैसे ई-रुपी, e-BG इत्यादि। साथ ही सरकार द्वारा e-BG को प्रमोट करने हेतु गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी कर नियमों में भी संशोधन किया गया है। बैंकों से निवेदन है कि इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दें।
- Integrated Financial Management System (IFMS)- राज्य सरकार, राज्य के सभी public finances को IFMS से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों के अतिरिक्त पैरा-स्टेट सगठनों जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs), स्थानीय निकाय इत्यादि को भी IFMS से जोड़ना चाहती है। इस हेतु जल्द ही वित्त विभाग, राजस्थान सरकार SOP जारी करेगा। सभी बैंकों से अनुरोध है की इस हेतु तैयारी प्रारम्भ करें।
- पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) से समय-समय पर शिकायत प्राप्त होती है कि बैंकों की तरफ से उन्हे ऋण प्रदान करने की प्रतिबद्धता होने के बावजूद भी लोन नहीं दिया जाता अथवा ऋण देने की अनिच्छा रहती है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) को समय पर पर्याप्त राशि का ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार सदन को संबोधित किया-

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंच को थिंक-टैंक के रूप में विकसित करने की अनुशंसा की थी। इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थिंक-टैंक समिति का गठन किया गया है जिसकी अब तक की बैठकों में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कार्यालय के सशक्तिकरण, एसएलबीसी के अजेंडा में सुधार, डाटा एनालिसिस इत्यादि बिन्दुओं पर विवेचना की गयी है। थिंक टैंक समिति इसी प्रकार आगे भी अन्य संबन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवेचना करती रहेगी।
- हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, ज़िला विकास प्रबन्धकों एवं आर-सेटी निदेशकों हेतु उदयपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसके दौरान कई महावपूर्ण संबन्धित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी। राज्य के अग्रणी बैंकों से निवेदन है कि उनके अंतर्गत अग्रणी ज़िला कार्यालय को Appropriate Infrastructure प्रदान कर सशक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ। डाटा एनालिसिस करने हेतु अग्रणी ज़िला कार्यालय में सक्षम स्टाफ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें क्योंकि डाटा एनालिसिस के माध्यम से जिलों में हो रहे विकास को बेहतर समझा जा सकता है। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं डीसीसी संयोजक बैंकों से अग्रणी ज़िला कार्यालय के स्टाफ की capacity building पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

- आर-सेटी द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम अति-सामान्य हैं जिनके माध्यम से रोजगार-सृजन के अवसर बेहद अल्प हैं। आर-सेटी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि आर-सेटी प्रशिक्षण में मोबाइल मरम्मत, घरेलू विद्युत उपकरण की मरम्मत इत्यादि जैसे विविध कार्यों का प्रशिक्षण शामिल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुमुखी बनाएँ। साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की भी सतत निगरानी करें।
- आर-सेटी क्रेडिट लिंकेज- स्वयं सहायता समूहों की वो महिलाएं जिनका अन्य योजनाओं में credit linkage किया जा चुका है, किन्तु जो आर-सेटी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के अतिरिक्त अधिकतर आर-सेटी का credit linkage 10% से कम है जो चिंताजनक है। इसमे सुधार करने हेतु गंभीरता से प्रयत्न करें।

(कार्यवाही: समस्त आर-सेटी संयोजक बैंक)

- लीड बैंकों के अतिरिक्त सभी बैंकों से अनुरोध है कि आर-सेटी प्रशिक्षुओं को समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान करने में संकोच नहीं करें। साथ ही तकनीक-आधारित उपायों का प्रयोग कर आर-सेटी के प्रशिक्षुओं के ऋण की processing time & cost कम करने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- आर-सेटी के क्रेडिट लिंकेज सुधारने हेतु की गयी पहल - भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों के सहयोग से आर-सेटी, उदयपुर ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसकी समाप्ती से पहले लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक प्रदेश के मुख्य बैंकों के साथ मिलकर आर-सेटी के क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत है। सरकारी बैंकों ने कुछ क्षेत्रों में, जहां उनको आर-सेटी हैं, में विशेष अभियान के तहत आर-सेटी क्रेडिट लिंकेज पर कार्य करना

प्रारम्भ किया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इसी प्रकार अपने क्षेत्र (service area) में क्रेडिट लिंकेज पर विशेष ध्यान दें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 13-17 फरवरी, 2023 के दौरान वित्तीय साक्षारता सप्ताह मनाया था। वित्तीय साक्षारता एवं वित्तीय समावेशन हेतु सभी हितग्राहकों को सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। 06-10 मार्च, 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट जागरूकता सप्ताह मानाया जा रहा है, जिसकी थीम है- डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। साथ ही डिजिटल पेमेंट से संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों का प्रसार करना भी आवश्यक है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के 02 मार्च 2017 के परिपत्र के संदर्भ में सभी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षारता शिविरों का आयोजन करना आवश्यक है। किन्तु कई ग्रामीण शाखाएँ निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शिविरों का आयोजन नहीं कर रहे हैं। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं को निर्देशित करें कि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाए। साथ ही वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत क्रेडिट अनुशासन के बारे में भी जागरूकता प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- कृषि क्षेत्र- भारत सरकार ने इस बार रु 20 ट्रिलियन कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने भी कृषि और संबन्धित गतिविधियों हेतु अपना बजट आवंटन 10% बढ़ाया है। गरीब किसानों का विकास देश के एकीकृत विकास हेतु अति महत्वपूर्ण है। सभी बैंक इस उद्देश्य हेतु अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- MSME- बैंक कम राशि के ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं। सभी बैंकों से अनुरोध है कि ऋण की प्रोसेसिंग एवं ऑपरेटिंग कोस्ट कम करने के लिए तकनीक-आधारित उपायों का प्रयोग करें एवं एमएसएमई वर्ग को समय से पर्याप्त ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- Customer Service- पंजाब नेशनल बैंक की चोहिलावली शाखा (हनुमानगढ़) का नियमित संचालन नहीं हो पा रहा है जो गंभीर विषय है। संबन्धित विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लें एवं इसका समाधान करें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

- डीसीसी/ डीएलआरसी बैठकों में कई बैंकों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं। सभी बैंकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ज़िले की प्रत्येक तिमाही की डीसीसी/ डीएलआरसी की बैठकों में अपने ज़िला समन्वयक की पूरी तैयारी के साथ उपस्थिती सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- बैंकों से अनुरोध है कि अपने ग्राहकों की शिकायतों का उचित निवारण अपने स्तर पर समय से करना सुनिश्चित करें ताकि शिकायत उच्च स्तर तक escalate ना हो।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- आर-सेटी द्वारा अपर्याप्त क्रेडिट लिंकेज किया जाना आर-सेटी एवं बैंकों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है। आवश्यकता है कि आर-सेटी को सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और वे जनसमर्थ पोर्टल इत्यादि अन्य परिष्कृत प्रणालियों का प्रयोग कर ग्राहकों को उनकी जरूरतों के आधार पर सीधे बैंकों से जोड़ने का प्रयास करें।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- आर-सेटी की मानव संसाधन आवश्यकताओं को अद्यतन करने की आवश्यकता है जिससे वह आज की प्रशिक्षण संबन्धित जरूरतों को पूरा कर सकें।
- डीसीसी/ डीएलआरसी बैठकों का आयोजन ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता में संबन्धित आर-सेटी में किया जाना चाहिए जिससे ज़िला प्रशासन एवं बैंकर्स को आर-सेटी की वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके।
- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक गतिशील एवं सक्षम होने चाहिए जिससे वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वाह कर सकें।
- डीसीसी/ डीएलआरसी बैठकों के संचालन की monitoring करने हेतु उपयुक्त प्रणाली होनी चाहिए जिसकी सूचना संबन्धित सरकारी विभाग को प्रदान की जा सके जिससे इनमे चर्चित किए जाने वाले मुद्दे जैसे आर-सेटी के मुद्दे पर मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में होने वाली द्वैमासिक बैठक में भी विवेचना की जा सके।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की विशेषताओं से सदन को अवगत कराते हुये सूचित किया कि उक्त योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृति एवं वितरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए हैं। किन्तु अन्य बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति दर काफी कम है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना के आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृत किए गए आवेदनों में बिना विलंब के ऋण वितरण करें।
- मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक एवं एक्सिस बैंक का प्रदर्शन असंतोषजनक है। भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, एचडीएफ़सी बैंक का प्रदर्शन सरहनीय है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक राज्य के उद्योगीकरण में अपनी भूमिका को पूर्ण निष्ठा से निभाएँ।
- PMEGP के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक का प्रदर्शन असंतोषजनक है। सभी बैंक इस योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने महाप्रबंधक, नाबार्ड को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुये कहा कि-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक साख योजना को नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर में निर्धारित रु 2.75 लाख करोड़ के लक्ष्य के अनुसार बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बैंक, कृषि निवेश ऋण को कुल कृषि ऋण के सापेक्ष 40% के स्तर तक पहुंचाने हेतु प्रयास करें एवं वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- नाबार्ड द्वारा मार्च, 2023 के पहले सप्ताह तक बैंकों, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं को रु 18,450 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की है। साथ ही Tribal Development Fund, Watershed Development Fund, Livelihood Entreprenuership Development Programme इत्यादि जैसी विकास-संबंधी पहलों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में credit-absorption बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से अनुरोध है कि नाबार्ड की इन पहलों में सहयोग प्रदान करें एवं इनका उपयोग करते हुए कृषि निवेश ऋण को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- नाबार्ड द्वारा राज्य में 'एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु सेंट्रल सैक्टर स्कीम' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गत 3 वर्षों में राज्य में 119 एफ़पीओ का गठन किया गया है। NABSANRAKSHAN के माध्यम से बैंकों द्वारा FPOs को दिये जाने वाले ऋण पर credit guarantee प्रदान की जाती है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि NABSANRAKSHAN पर पंजीकरण करवाएँ एवं FPOs की वृद्धि में सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- PACS Computerisation प्रोजेक्ट, केंद्रीय सरकार की Flag-ship योजना है जिसके तहत राज्य के सभी PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) को computerise किया जाएगा। प्रारम्भिक चरण में 3,244 PACS को computerize किया जाएगा।
- राजस्थान कृषि क्षेत्र में अग्रिम है एवं वर्ष 2023 'International Year of Millets' के रूप में मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में सभी बैंकों से अनुरोध है कि मोटे अनाज के उत्पादन एवं संबन्धित खाद्य प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाएँ। साथ ही फसल-विविधिकरण पर भी ध्यान दें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- सभी बैंक अपने ग्राहकों में भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाएँ। साथ ही सब्सिडि क्लेम हेतु नाबार्ड को समय से आवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन निधि (FIF) के तहत माइक्रो एटीएम, POS उपकरण, मोबाइल वेन इत्यादि हेतु सहायता राशि प्रदान करता है। अधिक जानकारी हेतु नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबन्धकों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। साथ ही जिन बैंकों को नाबार्ड से सहायता राशि प्राप्त हुयी है, उस राशि का उपयोग करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 155th SLBC Meeting (27.12.2022)

सर्वप्रथम उन्होने बताया कि दिनांक 27.12.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.01.2023 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Support required from State Governement

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने का मुद्दा लंबित है। पिछली तिमाही की एसएलबीसी की बैठक में संबन्धित विभाग ने उक्त संशोधन करने का आश्वासन दिया था।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

RACO RODA & SARFAESI Act के तहत वसूली में सहयोग अपेक्षित

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- प्रकरण बकाया दिनांक 31.12.2022 तक

  RACO RODA - 1,47,264 **Cases Amt. Rs.** 3,288 **Cr**

  SARFAESI Act - 2,085 **Cases Amt. Ra.** 414 **Cr.**
- विभिन्न जिलों में एसडीएम/तहसीलदार द्वारा राको-रोडा के नए केस स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं एवं मौजूदा केसों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की सितम्बर एवं दिसम्बर 2022 तिमाही की बैठक विभाग द्वारा समय प्रदान नहीं कर पाने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी है। उन्होने राजस्व विभाग से उक्त उपसमिति का आयोजन करवाने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- उनके विभाग द्वारा PDR Act, 1952 में संशोधन से संबंधी पत्रावली वित्त विभाग को संशोधन हेतु आगे भेजी हुई है, उच्चाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

Krishi Rin Rahan Portal

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार से कृषि ऋण रहन पोर्टल को सभी जिलो में लागू करने एवं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया। साथ ही जयपुर व

झुंझुनु जिले में कृषि ऋण रहन पोर्टल में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **भू-प्रबंधन विभाग** की टिप्पणी- जयपुर व झुंझुनु जिले में कृषि ऋण रहन पोर्टल 5-7 दिनों में पुनः चालू हो जाने की संभावना है।

Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को सूचित किया कि-

- सदस्य बैंक, बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगाने वाले शुल्क में छूट चाहते है।
- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 08.07.2022 व 24.08.2022 के माध्यम से अवगत करवाया है कि निकाय क्षेत्र में स्थित बैंक परिसरों के बाहर लगने वाले ग्लो साइन बोर्ड्स पर लगने वाले शुल्क में छूट दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 के अंतर्गत केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की भूमि, भवन जिनका प्रयोग मात्र लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है वहीं छूट प्राप्त है। बैंक, केंद्र सरकार का कोई लोक प्रयोजन संबंधी विभाग नहीं है।
- भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र के भाग **II**-खण्ड 3-उप-खण्ड(**ii**) की अधिसूचना संख्या 5644 दिनांक 15.12.2022 में पुनः बैंकिंग उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप आगामी छः माह के लिए बढ़ा दिया है। अतः बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जानी चाहिये।
- विभिन्न बैंक शाखाओं में "विज्ञापन शुल्क" के रूप में डिमांड नोटिस प्राप्त हो रहे है।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी-** जिस प्रकार राज्य सरकार बैंकों से सभी सरकारी योजनाओं के तहत अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा करती है, उसी प्रकार वह ग्लो साइन बोर्ड एवं बैंकों से संबन्धित अन्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही सकारात्मक निस्तारण करे।

प्रमुख शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने उक्त मुद्दे पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया।

आर-सेटी

प्रतिनिधि, **राजीविका**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि-

- डुंगरपुर ज़िले के कलक्टर द्वारा Group-3 के संयुक्त शासन सचिव से पत्र के माध्यम से रु 58,930 के ऑडिट प्रभार के waiver करने हेतु अनुशंसा की गयी है।
- MoRD, भारत सरकार ने आर-सेटी के लंबित क्लेम में से रु 13.22 करोड़ का fund allocation कर दिया है जो राशि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को हस्तांतरित हो गयी है। यह गत तीन वित्तीय वर्षों की क्लेम राशि है। वित्त विभाग द्वारा राजीविका विभाग को फ़ंड रिलीज़ होते ही बैंकों

को उनके क्लेम-बकाया के अनुपात में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके पश्चात बची हुई क्लेम राशि हेतु विभाग द्वारा पुनः भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

(कार्यवाही: राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रमुख शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि आर-सेटी के सशक्तिकरण हेतु लंबित सभी मुद्दो के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करे।

<u>ग्रामीणों द्वारा जबरन बंद शाखा- PNB चोहिलावली (हनुमानगढ़) को पुनः खुलवाने के संबंध में</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को ग्रामीणों द्वारा जबरन बंद पंजाब नेशनल बैंक की चोहिलावली (हनुमानगढ़) शाखा के संबंध में अवगत कराया।

प्रतिनिधि, **गृह विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार चोहिलावली शाखा के पीड़ित किसान, केसीसी एवं भारत माला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं।.

महाप्रबंधक, **पंजाब नेशनल बैंक** ने सूचित किया कि दिनांक 30.06.2022 को धोखा-धड़ी का पता लगने के बाद सात दोषियों को बैंक द्वारा निलंबित कर दिया गया है एवं मुख्य दोषी पुलिस की हिरासत में है। रु. 6.6 करोड़ की कुल धोखा-धड़ी की राशि में से रु. 4.58 करोड़ का भुगतान बैंक द्वारा पीड़ितों को कर दिया गया है। दोषियों के विरुद्ध बैंक स्तर पर जांच करने एवं गलत खातों से पैसों की वसूली करने हेतु शाखा का खोला जाना एवं सुगम संचालन आवश्यक है। किन्तु स्थानीय प्रशासन से अनेकों बार शाखा खुलवाने के लिए सहयोग का अनुरोध करने के पश्चात भी शाखा के बाहर 10-15 लोग धरना दे रहे हैं एवं शाखा का संचालन बधित कर रहे हैं।

प्रमुख शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करके शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>Support Required from Banks</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया-

- एलडीएम को इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त स्टाफ प्रदान करके सशक्त करना। साथ ही गतिशील एवं सक्षम स्टाफ को ही अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के रूप में नियुक्त करना।

  (कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक साख योजना को समयबद्ध तरीके से और पीएलपी-एसीपी-कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप तैयार करना ।

  (कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)
- कृषि के तहत निवेश ऋण (सावधि ऋण) में वृद्धि कर 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के स्तर तक पहुंचाना।
- डीएलआरसी/डीसीसी बैठकों में बैंकों के जिला समन्वयकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सभी लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त क्रेडिट प्रदान करना।

- PMFME योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) को बढ़ावा देना।
- जिलों के सीडी अनुपात में सुधार करना।
- राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना :
  - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (IGSCCY),
  - मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY),
  - डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना - 2022 (BRUPY),
  - इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPY) आदि।
- डिजिटल वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर ध्यान देना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

Setting up of Brick and Mortar Branches Status as on 02.03.2023

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में 95 स्थानों को ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित किया गया था और उसी के अनुसार एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा सदस्य बैंकों को आवंटित किया गया है। उन्होने सूचित किया कि 95 केन्द्रों में से 29 केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 02.03.2023 तक 49 केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं जिनमे से 39 शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है एवं 17 केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है।

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया कि सथाना से 6 किमी की दूरी पर उनके बैंक की विजयनगर शाखा कार्यरत है, इसलिए बैंक के उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त केंद्र पर बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भोजसर छोटा में ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलने की अनुमति शीर्ष प्रबंधन से प्राप्त हो गयी है एवं जल्द ही शाखा खोल देंगे।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सदन को सूचित किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से उक्त मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निर्देशित किया है। वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के हितग्राहियों द्वारा लिये गये निर्णय पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कार्यवाही अपेक्षित है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी हितग्राही यथा केंद्र एवं राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड इत्यादि की सहमति से जनहित को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ग्राम सथाना में ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने हेतु निर्देशित किया एवं संयोजक एसएलबीसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख से व्यक्तिगत रूप से बात कर उक्त मुद्दे का शीघ्र सकारात्मक समाधान निकालने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एसएलबीसी, राजस्थान)

प्रतिनिधि, बंधन बैंक ने सूचित किया कि वह दिनांक 31.03.2023 तक दोनों शाखाएँ खोल देंगे।

प्रतिनिधि, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सूचित किया कि वह एक शाखा 1-2 दिनों में खोल देंगे। दूसरी शाखा में उचित शाखा परिसर नहीं मिल पा रहा है एवं उन्होने स्थानीय प्रशासन से शाखा खोलने हेतु परिसर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

प्रतिनिधि, **एचडीएफ़सी** बैंक ने दिनांक 25.03.2023 तक तीनों केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखाएँ खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने पाँच केन्द्रों पर 27.03.2023 से पूर्व शाखा खोलने का आश्वासन दिया एवं सूचित किया कि एक केंद्र पर उचित शाखा परिसर नहीं मिल पा रहा है एवं उन्होने स्थानीय प्रशासन से शाखा खोलने हेतु परिसर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने सूचित किया कि आवंटित केंद्र पर शाखा खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा हुआ है।

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने सूचित किया कि स्थानीय मुद्दे के कारण आवंटित केंद्र पर शाखा खोलने में विलंब हो रहा है एवं वह जल्दी से जल्दी उक्त केंद्र पर शाखा खोलने हेतु प्रयासरत है।

Special 6 month campaign at Gram Panchayat (GP) Level under TFIIP

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि आकांक्षी जिलों में TFIIP के लक्ष्यों की उपलब्धि करने के उद्देश्य से दिनांक 15.02.2023 से 15.08.2023 तक चयनित जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर 6 माह के विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने सभी बैंकों एवं संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया उक्त अभियान में TFIIP के सातों KPI के तहत सराहनीय प्रदर्शन करते हुये TFIIP के लक्ष्य उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

KPIs identified under Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP):

1. Operative CASA accounts per lakh population
2. PMJJBY enrolments per lakh population
3. PMSBY enrolments per lakh population
4. APY subscribers per lakh population
5. Villages not having banking touch point within 5 km
6. Financial and Digital Literacy
7. Loans under MUDRA, Stand Up India, SVANidhi Scheme, KCC etc.

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बाराँ, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही)

Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) Progress as on 31.01.2023

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि प्रति लाख जनसंख्या पर सक्रिय CASA खातों में आकांक्षी जिलों में संतोषजनक प्रगति है। प्रति लाख जनसंख्या पर PMJJBY खातों में धौलपुर एवं करौली जिलों में 75% से कम लक्ष्य उपलब्धि है जो कि प्रदर्शन असंतोषजनक है। प्रति लाख जनसंख्या पर PMSBY खातों में धौलपुर, जैसलमेर एवं करौली जिलों का प्रदर्शन असंतोषजनक

है। प्रति लाख जनसंख्या पर APY खातों में जैसलमेर ज़िले का प्रदर्शन असंतोषजनक है। उन्होने कम प्रगति वाले जिलों में कार्यरत बैंकों एवं संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से TFIIP से समस्त मापदण्डों में प्रदर्शन सुधारते हुये लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, धौलपुर, जैसलमेर एवं करौली)

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोष जनक है-

Parameters	Dec, 2019	Dec, 2020	Dec, 2021	March, 2022	Dec, 2022*
No. of Branches (new Br in Yr.)	8,061 (151)	8,173 (69)	8,228 (77)	8,315 (187)	8,510 (253)
*Around 67.81% branches in Rural & Semi Urban.					
					Amt. in Rs. Crore
Deposits (% Y-o-Y Growth)	4,25,248 (11.03%)	4,75,448 (11.80%)	5,26,040 (10.64%)	5,47,105 (10.43%)	5,87,871 (11.75%)
Advances (% Y-o-Y Growth)	3,52,168 (10.93%)	3,92,293 (11.39%	4,38,729 (11.84%)	4,66,511 (14.08%)	5,20,329 (18.60%)
CD Ratio	85.16%	84.39%	84.86%	87.14%	88.51%
PS Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	2,25,177 (7.69%) (63.94%)	2,50,450 (11.22%) (63.84%)	2,84,757 (13.70%) (64.91%)	3,00,798 (16.98%) (64.48%)	3,16,957 (11.31%) (60.91%)
Agri. Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	1,06,744 (3.90%) (30.31%)	1,17,690 (10.25%) (30.00%)	1,30,166 (10.60%) (29.67%)	1,37,100 (12.83%) (29.39%)	1,41,942 (9.05%) (27.28%)
MSME Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	80,090 (6.37%) (22.74%)	92,481 (15.47%) (23.57%)	1,13,347 (22.56%) (25.84%)	1,20,943 (27.37%) (25.93%)	1,35,837 (19.84%) (26.11%)

Achievement against stipulated benchmark on December 2022

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में 1.37% की वृद्धि हुई है।
- कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी में 3.57% की गिरावट आई। हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में रु. 16,159 करोड़ की बढ़ौतरी हुयी ।
- एमएसएमई के तहत उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) की आवश्यकता के कारण माइक्रो खातों में 1.69% की कमी आई है। उन्होने सभी बैंकों से, मुख्य रूप से एसबीआई, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अनुरोध किया कि माइक्रो उद्यमों का यूआरसी लेकर उनका वर्गीकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: एसबीआई, यूको बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक व समस्त सदस्य बैंक)

- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में रु. 9,733 करोड़ की गिरावट आई है। (नेट गिरावट रु. 1,864 करोड़ रुपये)
- कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में 2.11% की गिरावट आई। हालांकि कृषि क्षेत्र outstanding में रु. 4,842 करोड़ की बढ़ौतरी हुयी।

Y-o-Y Growth under various parameters in Near by States (as on Sept 2022)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि निम्न मापदण्डों में अन्य राज्यों के सापेक्ष राजस्थान में प्रगति संतोष जनक है-

	Deposit	Advances	TPS	Agriculture	MSME
Rajasthan	11.75	18.60	11.31	9.05	19.84
U.P.	9.23	5.01	-2.65	0.72	4.76
Gujarat	10.09	12.67	15.30	11.00	19.11
Haryana	12.09	19.81	15.76	3.69	31.97

Snapshot of Sector wise Advanced in Near by States

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने दिनांक 31.12.2022 तक का निकटवर्ती राज्यों में अग्रिम का क्षेत्र-वार चित्रात्मक विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया।

Comparison of Credit to GDP & Deposit to GDP %age of the States

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक राजस्थान का credit-to-GDP अनुपात गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अधिक है किन्तु हरयाणा एवं पंजाब से कम है। साथ ही राजस्थान का Deposit-to-GDP अनुपात उक्त सभी राज्यों से कम है। वित्तीय साक्षारता के प्रसार से credit flow में वृद्धि कर के Deposit-to-GDP को सुधारा जा सकता है।

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
10	>100%	Barmer, Bhilwara, Bundi, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Nagaur, Pratapgarh, Sri Ganganagar and Tonk
16	71-100%	Alwar, Banswara, Baran, Bharatpur, Bikaner, Chittorgarh, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jodhpur, Kota, Pali, Rajsamand, Sawai Madhopur and Sikar
6	51-70%	Ajmer, Dholpur, Dungarpur, Jhunjhunu, Karauli and Udaipur
1	<50%	Sirohi

Districts having CD ratio lower than all India level (as on December, 22)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 11 जिलों यथा बांसवाड़ा, भरतपुर, पालि, झुञ्झुणु, कोटा, सिरोही, करौली, अजमेर, धोलपुर, उदयपुर एवं डुंगरपुर का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत (74.80%) से कम है। उन्होने सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बांसवाड़ा, भरतपुर, पालि, झुञ्झुणु, कोटा, सिरोही, करौली, अजमेर, धोलपुर, उदयपुर एवं डुंगरपुर)

इनमे से सिरोही एवं डुंगरपुर जिलों का सीडी अनुपात 60% के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से भी कम है जो चिंतनीय है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इन दोनों जिलों में credit flow को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां/ परियोजनाएं प्रारम्भ करें।

Districts having CD Ratio lower than 60%

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 60% से कम सीडी अनुपात वाले ज़िले डुंगरपुर एवं सिरोही का ब्लॉक-वार एवं बैंक वार विवरण सदन से सामने रखा।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- डुंगरपुर एवं सिरोही जिलों में सीडी अनुपात आरबीआई बेंचमार्क से अधिक लाने हेतु वार्षिक साख योजना बनाते समय इन जिलों में उपलब्ध क्षमता के आधार पर लक्ष्य आवंटित करें एवं सतत मोनिट्रिंग करें।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि अपनी शाखाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय एसएलबीसी में एजेंडा के मुद्दों पर भी चर्चा करें जिससे एसएलबीसी के प्रयास जमीनी स्तर पर परिलक्षित हों।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Comparative Development of the Districts: CRISIL Inclusix Index

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- दिसम्बर, 2022 तक राज्य में प्रति लाख जनसंख्या 12 शाखाएँ, 1,26,270 CASA खाते, 24,683 ऋण खाते एवं 30,221 बीमा (PMJJBY एवं PMSBY) हैं। सितंबर 2022 तिमाही के सापेक्ष उक्त मापदण्डों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
- 31 दिसम्बर 2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम शाखा पेनिट्रेशन वाले ज़िले जयपुर (20), श्रीगंगानगर (17), कोटा (15), अजमेर (15) एवं हनुमानगढ़ (15) हैं एवं न्यूनतम शाखा पेनिट्रेशन वाले ज़िले धौलपुर (6), बाड़मेर(8), प्रतापगढ़ (8), करौली (8) एवं बांसवाड़ा (8) हैं।
- 31 दिसम्बर 2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम डिपॉज़िट पेनिट्रेशन (प्रति लाख व्यक्ति CASA खातों की संख्या) वाले ज़िले जयपुर (1,59,043), जैसलमेर (1,41,707), भीलवाडा (1,36,582), श्री गंगानगर (1,34,801) एवं अजमेर (1,34,117) हैं एवं न्यूनतम डिपॉज़िट पेनिट्रेशन वाले ज़िले प्रतापगढ़ (1,10,333), धौलपुर (1,00,330), करौली (1,03,931), भरतपुर (1,08,185) एवं सिरोही (1,12,436) हैं।
- 31 दिसम्बर 2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले ज़िले जयपुर (44,130), हनुमानगढ़ (33,087), श्रीगंगानगर (32,154), बूंदी (31,414) एवं कोटा (31,166) हैं एवं न्यूनतम क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले ज़िले धौलपुर (8,257), करौली (11,701), सिरोही (12,699), भरतपुर (14,407) एवं बांसवाड़ा (14,608) हैं।
- 31 दिसम्बर 2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम बीमा पेनिट्रेशन वाले ज़िले कोटा (45,360), टोंक (42,991), राजसमंद (40,807), प्रतापगढ़ (40,169) एवं भीलवाड़ा (40775) हैं एवं न्यूनतम बीमा पेनिट्रेशन वाले ज़िले भरतपुर (19,640), धौलपुर (19,594), नागौर (22,846), करौली (23,235) एवं जालोर (24,718) हैं।

उन्होने न्यूनतम शाखा, डिपॉज़िट, क्रेडिट एवं बीमा पेनिट्रेशन वाले उक्त सभी जिलों को संबन्धित मापदंडों में सुधार करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, नागौर, सिरोही एवं भरतपुर)

उन्होने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि उक्त जिलों के जिला कलक्टर एवं अन्य संबन्धित ज़िला अधिकारियों से CRISIL Inclusix Index के मापदण्डों के तहत प्रगति करने हेतु सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने सभी बैंकों से से अनुरोध किया कि उक्त जिलों में CRISIL Inclusix Index के तहत प्रदर्शन में सुधार करने हेतु सभी शाखाओं का का मार्गदर्शन करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 31.12.2022)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 31.12.2022 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **26.56%, 6.97%, 7.66% एवं 99.97%** हैं।

दिनांक 31.12.2022 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत (23.85%) से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.93%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.19%), यूको बैंक (5.68%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (6.15%), भारतीय स्टेट बैंक (6.67%), केनरा बैंक (8.31%), बीआरकेजीबी (9.02%), आईडीबीआई (10.04%0, पंजाब और सिंध बैंक (12.38%), इंडियन बैंक (13.47%), बैंक ऑफ बड़ौदा (18.15%) एवं आईसीआईसीआई बैंक (20.00%)

उन्होने सूचित किया कि राज्य में कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण का **23.85%** है जिसे कम से कम 40% तक ले जाने हेतु सभी बैंकों से सतत प्रयत्न करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Annual Credit Plan 2022-23</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2022-23 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु॰ 2,29,076 करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तिमाही तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 78.85%
- MSME- 119.40%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 68.13%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 90.46%

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एजेंसी-वार वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति निम्नानुसार सूचित की-

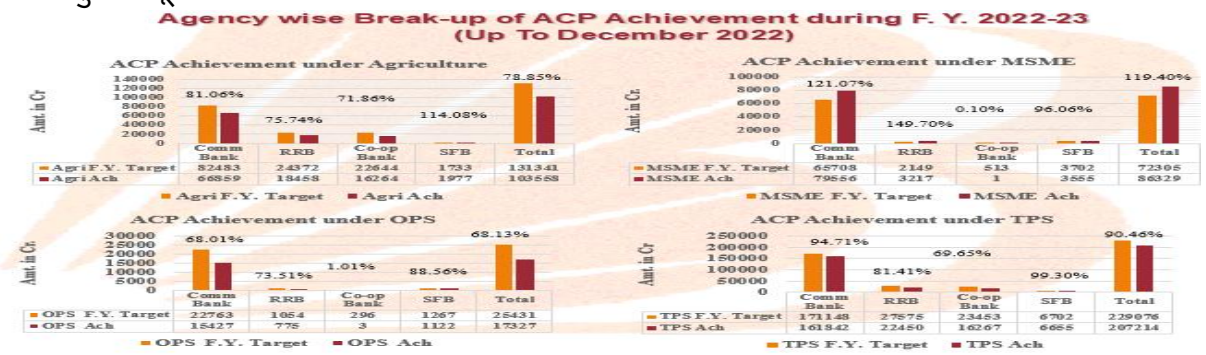

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत दिनांक 31.12.2022 तक 65% से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (19.27%), राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (1.55%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (51.21%) एवं इंडसइंड बैंक (36.08%) से लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एवं आरबीएल बैंक)

प्रतिनिधि, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने सूचित किया कि बैंक के केंद्रीय कार्यालय में नवीकृत ऋण खातों का डाटा अद्यतित नहीं होने के कारण बैंक की प्रगति कम परिलक्षित हो रही है। उन्होने मार्च तिमाही के अंत तक वार्षिक साख योजना के लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, पंजाब और सिंध बैंक ने मार्च तिमाही के अंत तक वार्षिक साख योजना के लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का आश्वासन दिया।

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 01.03.2023 तक की प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
30.09.2022	69,15,500	21,49,542 (31%)	96,73,911	51,55,422 (53%)	56,33,175	7,92,742 (14%)
01.03.2023	69,15,500	26,39,039 (38%)	96,73,911	59,49,123 (62%)	56,33,175	8,95,189 (16%)
PROGRESS		4,89,497		7,93,701		1,02,447

सभी बैंकों से जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के संतृप्ति अभियान के तहत सितंबर 2024 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna:

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:

Progress upto 28.02.2023						
Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 28.02.2023	% Ach.
PSB		4142	80	331360	448494	135%
RRB		1575	80	126000	130308	103%
Small Finance Bank		247	50	12350	7665	62%
Private	Other Private Banks	349	30	10470	4391	42%
	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	910	80	72800	8982	12%
Co-Op.		462	20	9240	7	0%
Total		7685		562220	599847	107%
* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 5,62,220 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2023 तक 5,99,847 (107%) नामांकन किए गए हैं। अटल पेंशन योजनान्तर्गत एजेंसी-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- वाणिज्यिक बैंक-135%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-103%

- स्माल फ़ाइनेंस बैंक-62%
- एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एक्सिस बैंक-12%
- अन्य निजी बैंक- 42%
- सहकारी बैंक-0%

अटल पेंशन योजना के तहत दिनांक 28.02.2023 तक कम प्रगति वाले बैंक यथा इंडियन बैंक (72%), पंजाब नेशनल बैंक (59%), यूको बैंक (58%), आईडीबीआई बैंक (19%), एचडीएफ़सी बैंक (14%), आईसीआईसीआई बैंक (12%) एवं एक्सिस बैंक (9%) से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक)

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

जिला करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर एवं सिरोही को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है जिनमे से करौली ज़िले में 100% डिजिटलिकरण हो गया है। 100% डिजिटल ज़िलों हेतु करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमर एवं सिरोही की प्रगति निम्नानुसार है:

Status of 100 % Digital District - Karauli - Ajmer - Dholpur - Sirohi - Jaisalmer

Sr. No.	District	Months	Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for Businesses (Current Accounts)	
			Eligible Operative Savings Accounts		% Coverage with at least one of the digital modes of payment				Total No. of Eligible Operative Current/ Business Accounts	% Coverage with at least one of the digital modes of payment
			No. of Accounts	Of which, no. of women accounts	Total No. of Accounts covered	All Accounts	Out of total no. of women accounts (G6), no of women accounts covered	women accounts		
1	Karauli	Jan-23	12.89 Lakhs	5.73 Lakhs	12.87 Lakhs	99.81	5.71 Lakhs	99.67	0.16 Lakhs	99.41
2	Ajmer	Dec-22	36.54 Lakhs	15.98 Lakhs	31.73 Lakhs	86.84	11.75 Lakhs	73.55	1.24 Lakhs	77.37
3	Dholpur	Dec-22	10.62 Lakhs	4.89 Lakhs	9.72 Lakhs	91.49	4.43 Lakhs	90.64	0.17 Lakhs	85.51
4	Sirohi	Dec-22	9.46 Lakhs	4.07 Lakhs	8.61 Lakhs	91.01	3.72 Lakhs	91.6	0.19 Lakhs	73.41
5	Jaisalmer	Dec-22	6.74 Lakhs	2.71 Lakhs	6.10 Lakhs	90.44	2.44 Lakhs	89.95	0.19 Lakhs	66.39

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बैठक के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-महाप्रबंधक एवं बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की अनुमति से बाराँ ज़िले (लीड बैंक - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित करने की घोषणा की। उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं सभी बैंकों से उक्त जिलों को निश्चित समयावधि में 100% डिजिटल ज़िला बनाने हेतु सतत प्रयत्न करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर, सिरोही, जैसलमर एवं बाराँ)

KCC Saturation Drive: District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए 15 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान को फिर से शुरू करना सूचित किया है जिसके तहत प्रगति निम्नानुसार है:

Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry & Fisheries from 15.11.2021 to 17.02.2023								
Sr. No.	Particulars			Cumulative No. of Applications under AHD & Fisheries				
				Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Pending
A	All Banks	Animal Husbandry	09.12.2022	1,41,884	1,34,841	75,473	58,309	1,059
			17.02.2023	1,56,049	1,48,973	89,129	58,962	882
			Progress	**14,165**	**14,132**	**13,656**	**653**	**-177**
B		Fisheries	09.12.2022	448	445	92	337	16
			17.02.2023	516	513	156	346	11
			Progress	**68**	**68**	**64**	**9**	**-5**

सभी बैंकों से उक्त अभियान के तहत पात्र पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों के लंबित आवेदनों का समय से निस्तारण करते हुये सराहनीय प्रगति करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,03,787 आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से 74,975 आवेदनों में रु. 8,092.25 लाख वितरित किए गए हैं। 28,812 स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है।

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 01 03 2023					Low Performing Banks as on 01 03 2023				
Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Account)	Total Disb (Account)	% disbusement against Target	Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Account)	Total Disb (Account)	% disbusement against Target
1	Bank of India	4330	5040	116.40	1	IndusInd Bank	4161	0	0.00
2	Bank of Baroda	17880	16574	92.70	2	Yes Bank Ltd.	3573	0	0.00
3	State Bank of India	33931	29794	87.81	3	Bandhan Bank Ltd.	8029	1	0.01
4	Bank of Maharashtra	1260	700	55.56	4	Axis Bank	6515	6	0.09
5	Central Bank of India	5423	2973	54.82	5	Kotak Mahindra Bank	2396	7	0.29
6	Indian Bank	4582	1786	38.98	6	AU Small Finance bank	7230	115	1.59
7	Indian Overseas Bank	2312	847	36.63	7	ICICI Bank	12989	269	2.07
8	Union Bank of India	9248	3325	35.95	8	HDFC Bank	7903	302	3.82

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

कुल आवेदन स्वीकृति में एजेंसी-वार बैंकों का हिस्सा इस प्रकार है - वाणिज्यिक बैंक- 93.53%, निजी बैंक- 3.10%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 3.01%, स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 0.35%.

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23.02.2023 तक रु 15,572.68 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 15,20,473 खातों में रु 13,760.41 करोड़ (71.65%) का ऋण वितरण किया गया।

दिनांक 23.02.2023 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	9,97,332 (65%)	3,164.30
2	Kishore	4,66,024 (31%)	6,301.28

3	Tarun	57,117 (4%)	4,294.83
	Total	15,20,473 (100%)	13,760.41

सभी बैंकों से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>स्टैंड अप इंडिया योजना</u> <u>Stand Up India Scheme (SUI)</u>

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 28.02.2023 तक राज्य में 8,760 आवेदनों में राशि रु. 1,971.61 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए एवं 4,766 खातों में रु 844.31 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 28.02.2023 तक रु. 562.94 करोड़ के 2,543 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं 589 खातों में रु 109.67 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>National Rural Livelihood Mission</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य 91,100 के सापेक्ष दिनांक 01.03.2023 तक 73,455 खातों (80.63%) में रु 1,152.92 करोड़ (80.06%) का ऋण वितरण किया गया है।

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 01.03.2023					Low Performing Major Banks as on 01.03.2023				
S. No.	Particulars	Target A/c	Sanction A/c	% Sanctioned against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Sanction A/c	% Sanctioned against Target
1	HDFC BANK LTD	4625	9096	196.67	1	PUNJAB AND SIND BANK	80	0	0.00
2	INDIAN BANK	1010	1282	126.93	2	AXIS BANK	35	0	0.00
3	BRKGB	20500	22873	111.58	3	RSCB	2000	0	0.00
4	ICICI BANK LTD	11000	11482	104.38	4	INDIAN OVERSEAS BANK	345	16	4.64
5	BANK OF BARODA	12000	12412	103.43	5	UNION BANK OF INDIA	1700	403	23.71
6	CANARA BANK	1260	776	61.59	6	RMGB	12000	3285	27.38
7	PUNJAB NATIONAL BANK	7480	3946	52.75	7	BANK OF MAHARASHTRA	165	56	33.94
8	STATE BANK OF INDIA	11500	5775	50.22	8	UCO BANK	1470	518	35.24

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, एक्सिस बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं यूको बैंक)

NRLM योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों ने 36.37%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 35.61%, निजी बैंक ने 28.01% एवं सहकारी बैंक ने 0.00% ऋण प्रदान किए हैं।

DAY- National Urban Livelihood Mission (NULM)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 6,000 व्यक्तियों एवं 2,763 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 01.03.2023 तक 1,833 (30.55%) व्यक्तियों एवं 567 (20.52%) स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है।

Prime Minister Employment Generation Programme

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 01.03.2023 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bankwise PMEGP progress as on 01.03.2023										(Amt. Rs. In Cr.)		
Sr. No.	Margin Money Targets for F.Y. 22-23	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed		
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach
A	114.48	7382	371.45	2797	170.50	148.93	1813	101.88	89.00	1564	81.61	71.29

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 01.03.2023					Lowest Performing Banks under as on 01.03.2023				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed	Sr. No.	Banks	Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed
1	BANK OF BARODA	12.5	28.68	229.44	1	AU SMALL FIN BANK LTD	0.73	0.00	0.00
2	CENTRAL BANK OF INDIA	5.05	7.29	144.28	2	AXIS BANK LTD	2.50	0.00	0.00
3	CANARA BANK	5.30	5.66	106.71	3	ICICI BANK LIMITED	4.05	0.39	9.59
4	PUNJAB NATIONAL BANK	13.74	11.15	81.15	4	HDFC BANK	3.50	0.35	9.95
5	UNION BANK OF INDIA	6.20	4.33	69.82	5	BANK OF MAHARASHTRA	1.20	0.18	15.08
6	BRKGB	8.10	5.17	63.87	6	IDBI BANK	2.20	0.35	15.73
7	PUNJAB AND SIND BANK	1.49	0.93	62.74	7	INDIAN BANK	3.70	1.13	30.48
8	UCO BANK	4.60	2.79	60.75	8	RMGB	6.54	2.11	32.27
Source: PMEGP Portal									

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक एवं एक्सिस बैंक)

योजनांतर्गत वाणिज्यिक बैंक का 89.44%, निजी बैंक द्वारा 2.96%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 7.49% एवं सहकारी बैंकों का 0.00% योगदान है।

PMFME Scheme

दिनांक 28.02.2022 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Progress under PMFME during FY 2022-23 as on 28-02-2022			
S. No.	Particulars	Target (No. of A/c)	Achievement
A	Public Sector Bank Total	1524	199
B	Private Sector Bank Total	418	32
C	Regional Rural Bank Total	321	22
D	Co-Operative Bank Total	43	0
E	Small Finance Bank Total	75	9
	Rajasthan Total	**2383**	**262**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 01.03.2023 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 01.03.2023											(amt. in Rs. Cr.)
Sr. No.	Bank	Target F. Y. 2022-23	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		% Achievement
		Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANKS TOTAL	2054.19	432	462.05	306	263.77	115	142.85	191	120.92	12.84
B	PRIVATE SECTOR BANKS TOTAL	686.37	180	235.42	88	89.14	46	48.04	42	41.10	12.99
C	REGIONAL RURAL BANKS TOTAL	236.52	28	20.25	21	13.98	3	4.10	18	9.88	5.91
D	COOPERATIVE SECTOR BANKS TOTAL	182.02	20	2.21	2	0.15	2	0.15	0	0.00	0.08
E	SMALL FINANCE BANK TOTAL	72.42	24	31.28	13	14.86	4	6.70	9	8.16	20.52
F	OTHERS TOTAL	0	3	0.28	3	0.28	1	0.11	2	0.17	0.00
	RAJASTHAN TOTAL	**3231.52**	**687**	**751.49**	**433**	**382.18**	**171**	**201.95**	**262**	**180.24**	**11.83**

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna (IGSCCY)</u>

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में 5,00,000 के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 01.03.2023 तक कुल प्राप्त 3,72,796 आवेदनों के सापेक्ष कुल (IGSCCY+ PMMY) 1,80,914 आवेदनों में रु 530 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य का 36.18% है

IGSCCY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 01.03.2023							Low Performing Major Banks as on 01.03.2023						
S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% Sanctioned against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% Sanctioned against Target
			IGSCCY	PMMY	Total					IGSCCY	PMMY	Total	
		A/c	A/c	A/c	A/c				A/c	A/c	A/c	A/c	
1	INDUSIND BANK	7708	0	83300	83300	1080.70	1	YES BANK	6658	0	0	0	0.00
2	AXIS BANK	13742	1	17586	17587	127.98	2	UJJIVAN SMALL FINANCE BANK	1582	0	0	0	0.00
3	HDFC BANK	20448	706	15934	16640	81.38	3	RSCB	15584	0	0	0	0.00
4	BANK OF BARODA	47887	9452	4645	14097	29.44	4	KOTAK MAHINDRA BANK	5357	0	0	0	0.00
5	STATE BANK OF INDIA	99079	20348	3308	23656	23.88	5	JANA SMALL FINANCE BANK	664	0	0	0	0.00
6	UCO BANK	18275	1333	687	2020	11.05	6	IDFC FIRST BANK	1934	0	0	0	0.00
7	BANK OF MAHARASHTRA	4029	411	11	422	10.47	7	FEDERAL BANK	1046	0	0	0	0.00
8	PUNJAB NATIONAL BANK	53550	4817	434	5251	9.81	8	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	2601	0	0	0	0.00
9	CANARA BANK	23510	867	1365	2232	9.49	9	BANDHAN BANK	1745	0	0	0	0.00
10	INDIAN OVERSEAS BANK	7342	593	5	598	8.14	10	IDBI BANK	5587	59	0	59	1.06

कुल स्वीकृति में वाणिज्यिक बैंकों का 28.70%, निजी बैंकों का 65.73%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 1.35%, स्माल फ़ाइनेंस बैंक का 0.30% एवं अन्य बैंकों का 3.91% योगदान है।

सभी सदस्य बैंकों से योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है। साथ ही स्वीकृत किए हुये आवेदनों में समय से ऋण वितरण करने एवं पोर्टल पर अद्यतित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Mukhya Mantri Laghu udyog Protsahan Yojna (MLUPY)</u>

दिनांक 01.03.2023 तक MLUPY योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana									
S. No.	Particulars	Progess as on 01.03.23							(Amt. in Rs. Cr.)
		Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement		% Ach
		A/c	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	
A	Rajasthan	10780	17279	2740.43	9757	1522.57	8819	1522.21	81.81

MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 01.03.2023						Low Performing Major Banks as on 01.03.2023					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Sanctioned against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Sanctioned against Target
		Total App.	Total App.	Amt (In Cr)				Total App.	Total App.	Amt (In Cr)	
1	HDFC BANK	21	130	102.51	619.05	1	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	424	1	0.05	0.24
2	CANARA BANK	444	584	75.10	131.53	2	INDUSIND BANK	75	5	2.86	6.67
3	BANK OF BARODA	1076	1391	292.44	129.28	3	YES BANK	80	8	3.41	10.00
4	BRKGB	1026	1227	89.17	119.59	4	ICICI BANK LIMITED	579	90	70.40	15.54
5	IDBI BANK	179	201	19.94	112.29	5	BANK OF MAHARASHTRA	111	23	15.78	20.72
6	BANK OF INDIA	388	392	39.62	101.03	6	PUNJAB AND SIND BANK	110	29	7.90	26.36
7	AU SMALL FINANCE BANK	353	353	55.81	100.00	7	AXIS BANK	194	71	29.42	36.60
8	INDIAN OVERSEAS BANK	188	184	8.01	97.87	8	INDIAN BANK	278	118	17.46	42.45

कम प्रगति करने वाले बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध जय।

(कार्यवाही: इक्वीटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, एक्सिस बैंक एवं इंडियन बैंक)

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में वितरण करें। साथ ही समय से पोर्टल पर प्रगति को अद्यतित करें और सब्सिडी का दावा प्रेषित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivaasi Udyam Protsahan Yojna- 2022 (BRUPY)</u>

दिनांक 03.03.2023 तक उक्त योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan yojana-2022							
S. No.	Particulars	Progess as on 03.03.23 (Amt. in Rs. Cr.)					
		Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement	
		A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt
A	Rajasthan	544	193.17	34	16.99	17	3.99

उक्त योजनान्तर्गत सबसे अधिक अवाम सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 03.03.2023				Low Performing Major Banks as on 03.03.2023			
S. No.	Particulars	Sanctioned		S. No.	Particulars	Sanctioned	
		Total App.	Amt (In Cr)			Total App.	Amt (In Cr)
1	STATE BANK OF INDIA	9	290.00	1	BANK OF INDIA	0	0.00
2	BANK OF BARODA	8	850.95	2	CANARA BANK	0	0.00
3	UNION BANK OF INDIA	7	352.95	3	UCO BANK	0	0.00
4	RMGB	2	14.95	4	AU SMALL FINANCE BANK	0	0.00
5	PUNJAB NATIONAL BANK	2	11.60	5	INDIAN OVERSEAS BANK	0	0.00
6	CENTRAL BANK OF INDIA	2	68.70	6	HDFC BANK	0	0.00
7	BRKGB	2	19.55	7	Indian Bank	0	0.00

कम प्रदर्शन वाले उक्त बैंकों से अनुरोध है कि योजनांतरगत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूको बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडिया ओवरसीज़ बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, इंडियन बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 17.02.2023 तक 429 लाभार्थियों को रु. 27.60 करोड़ (42.90%) का ऋण वितरण किया गया है।

IMSUPY के तहत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Bank as on 17.02.2023						Top Performing Major Bank as on 17.02.2023					
Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications			Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications		
			A/c	Amt	% Ach				A/c	Amt	% Ach
1	BRKGB	89	236	12.33	265.17	1	AU SMALL FINANCE BANK	18	0	0.00	0.00
2	CENTRAL BANK OF INDIA	49	22	2.44	44.90	2	AXIS BANK	19	0	0.00	0.00
3	CANARA BANK	50	21	2.01	42.00	3	HDFC BANK	29	0	0.00	0.00
4	RMGB	49	19	0.65	38.78	4	Others	38	0	0.00	0.00
5	BANK OF BARODA	117	41	3.53	35.04	5	ICICI BANK LIMITED	39	2	0.07	5.13
6	UCO BANK	38	13	1.09	34.21	6	INDIAN OVERSEAS BANK	26	2	0.05	7.69
7	UNION BANK OF INDIA	56	16	1.20	28.57	7	PUNJAB AND SIND BANK	12	1	0.08	8.33
8	IDBI BANK	18	5	0.64	27.78	8	INDIAN BANK	38	4	0.11	10.53

कुल स्वीकृति में वाणिज्यिक बैंकों का 46.00%, निजी बैंकों का 1.60%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 6.40% एवं अन्य बैंकों का 0.00% योगदान है।

कम प्रगति वाले बैंकों से प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी, बीआरकेजीबी एवं समस्त स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2022-23 में दिसम्बर, 2022 तिमाही तक राज्य में 12,749 छात्रों को राशि रू 419.60 करोड़ के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.12.2022 तक 41,313 खातों में रु 2,264.72 करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 6621 खातों में रु 225.28 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

Sector wise NPA Position as on 31st December, 2022

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल- 4.09%

कृषि- 8.60%

एमएसएमई- 3.18%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 2.29%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 5.50%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 57.32%

कुल एमएसएमई- 20.30%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.22%

Comparison chart of NPA (%)

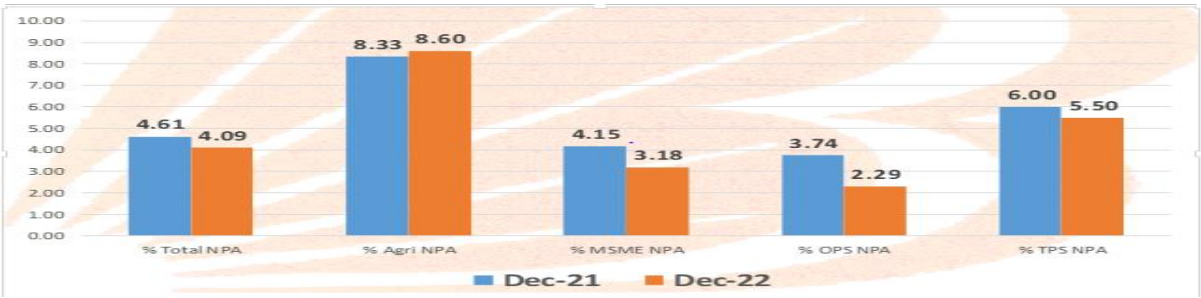

प्रतिनिधि, सिडबी ने उद्यमी मित्र पोर्टल पर सदन के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होने समस्त बैंकों से उद्यमी मित्र पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सदन के समक्ष महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होने राजस्थान राज्य ग्रामीण बैंक से औसत ऋण वितरण राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,50,000 रुपये करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजीविका, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि Common दस्तावेज़ तैयार करके सभी बैंकों को भेज दें जिससे बैंक अपने लीगल विभाग से उन्हे अनुमोदित करवा सकें। साथ ही उन्होने राजीविका विभाग को सूचित किया कि कई बार पहली डोज़ लेने के बाद लाभार्थी दूसरी डोज़ हेतु लाभार्थी बैंक वापस नहीं आता। उन्होने राजीविका से लाभार्थियों को दूसरी डोज़ का लाभ उठाने के संबंध में sensitize करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजीविका, राजस्थान सरकार)

Cyber Fraud

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन के समक्ष UPI ट्रैंज़ैक्शन में हो रहे साइबर फ्रौड पर प्रस्तुतीकरण दिया।

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।